ईएसआई कार्पोरेशन पैसा लेना जानती है, सुविधायें देना नहीं

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

देश भर के 3 करोड़ 39 लाख मज़दूरों से उनके वेतन का नियमित चार प्रतिशत वसूलने के बावजूद उन्हें पर्याप्त चिकित्सा सुविधायें देने से ईएसआई कार्पोरेशन किनारा करती आ रही है। इन बीमाकृत मज़दूरों पर आश्रित कुल 13 करोड़ 16 लाख लोग हैं। इन लोगों को चिकित्सा सेवायें देने के जो तय शुदा मानक हैं, कार्पोरेशन उनका खुलकर उल्लंघन करती आ रही है।

चिकित्सा सुविधायें देने के लिये कार्पोरेशन स्वयं 50 अस्पताल चलाती है तथा 110 अस्पताल राज्य सरकारों के द्वारा चलवाती है। इसके लिये राज्य सरकारों को कार्पोरेशन कुल खर्च का सात भाग देती है शेष आठवां भाग राज्य सरकारें वहन करती हैं। अधिकतर राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली चिकित्सा सेवायें निहायत दुर्दशा का शिकार बनी हुई है। उदाहरण के लिये फ़रीदाबाद का सेक्टर आठ का अस्पताल तथा कार्पोरेशन द्वारा अधिग्रहण करने से पहले एनएच तीन वाला अस्पताल भयंकर दुर्दशा के शिकार थे। इसी को देखते हुए एनएच तीन वाले अस्पताल को कार्पोरेशन ने अपने हाथ में लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्थापित किया।

फ़रीदाबाद तथा हैदराबाद वाले मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को छोड़कर कार्पोरेशन के शेष 48 अस्पताल भयंकर दुर्दशा के शिकार बने हुए हैं। इसका निकटतम उदाहरण गुड़गांव के दो अस्पताल हैं तथा दिल्ली का बसई दारापुर स्थित अस्पताल है।

दुर्दशा के अधिक विवरण में जाये बगैर फ़िलहाल इनमें उपलब्ध बिस्तरों की स्थिति का जायजा लेते हैं। कार्पोरेशन के इन 50 अस्पतालों में कुल 12440 बिस्तर स्वीकृत हैं जिनमें से मात्र 8835 बिस्तरें चालू हैं अर्थात इन पर मरीज़ों को लिटाया जा सकता है।

यहीं पर समझने वाली बात यह है कि कुल स्वीकृत बिस्तरों में से 3605 बिस्तर उपलब्ध ही नहीं हैं। इससे भी गंभीर एवं दुखदायी तथ्य यह है कि चालू बिस्तरों में से केवल 36 प्रतिशत यानी कुल 3180 बिस्तरों पर ही मरीज़ अपना इलाज करा पा रहे हैं। संदर्भवश डब्लूएचओ (विश्व स्वास्थ्य संगठन) के अनुसार प्रति 1000 लोगों पर तीन बिस्तर होने चाहिये। इस हिसाब से भारत की 138 करोड़ की आबादी पर बिस्तरों की संख्या 41 लाख 40 हजार होनी चाहिये। जबकि उपलब्ध हैं केवल 11 लाख 85 हजार। चलो यह तो भारत सरकार का मसला है जिसके पास जनता के इलाज पर खर्च करने को पैसा नहीं है। परन्तु ईएसआई कार्पोरेशन धन की कमी का बहाना नहीं ले सकती। इसके पास मज़दूरों के वेतन से वसूला गया एक लाख 37 हजार करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। डब्लूएचओ के मानकों के अनुसार ईएसआई कार्पोरेशन को अपने बीमाकृत मज़दूरों के लिये तीन लाख 94 हजार बिस्तर उपलब्ध कराने चाहिये। जबकि उपलब्ध केवल 27 हजार हैं। यह संख्या दोनों तरह के अस्पतालों को मिलाकर है।

डॉ. दीपक शर्मा जैसे निकृष्ट एवं हरामखोर जहां इंचार्ज होते हैं वहां बिस्तर खाली ही रहते हैं

मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि देश भर में 8835 चालू बिस्तरों में से केवल 36 प्रतिशत पर ही मरीज़ क्यों इलाज कराने को दाखिल हैं? जवाब स्पष्ट है कि मरीज़ वहीं दाखिल होता है जहां उसे अपने इलाज की कोई सम्भावना नज़र आती हो। जहां डॉक्टरों व अन्य स्टाफ़ की नीयत इलाज करने की ही न हो तो वहां कोई मरने के लिये दाखिल क्यों होगा?

इसका जीता-जागता उदाहरण बसई दारापुर के अस्पताल में देखा जा सकता है 600 बिस्तरों वाले इस अस्पताल में सन 2019 तक एक भी बिस्तर खाली नहीं रहता था, बल्कि बिस्तर खाली होने के इन्तजार में 20-30 मरीज़ कैजुअल्टी में स्ट्रेचरों व ज़मीन पर अपनी बारी के इन्तजार में पड़े रहते थे। आज उसी अस्पताल में आधे से अधिक बेड खाली पड़े हैं। यह कमाल किया डॉ. दीपक शर्मा ने। ये साहब 2019 के बाद वहां के चिकित्सा अधीक्षक रहे हैं। इनका एकमात्र लक्ष्य यह रहा था कि इस अस्पताल को फेल करना है। इन्होंने कभी भी आवश्यक साज़ो सामान की आपूर्ति ढंग से नहीं होने दी। जाहिर है कि जब डाक्टरों को आवश्यक चीजें ही उपलब्ध नहीं होंगी तो वे इलाज क्या करेंगे?

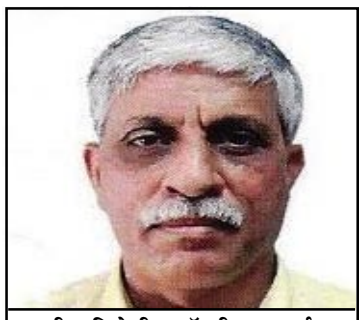

मरीज विरोधी : डॉ. दीपक शर्मा, एमबीबीएस

समझा जा सकता है कि इन हालात में कोई मरीज़ ऐसे अस्पताल में दाखिल होकर अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा? परिणामस्वरूप डॉ. दीपक शर्मा का जो लक्ष्य इस अस्पताल को उजाड़ने का था वह काफ़ी हद तक पूरा हो गया। डॉ. शर्मा की इसी 'उपलब्धि' से प्रसन्न होकर ईएसआई कार्पोरेशन ने उन्हें पदोन्नत करके मेडिकल कमिश्नरबना दिया। अब उनके हाथ में देश भर के 50 अस्पतालों को बर्बाद करने का लक्ष्य सौंपा गया है।

सरकारी नीतियों के विरोध में योग कोचों ने कराया अपना मुंडन

करनाल (रवि भाटिया) हरियाणा के योग कोच व योग सहायकों द्वारा लघु सचिवालय के सामने 13 जून से चल रहा है अनिश्चितकालीन राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन व क्रमिक अनशन के दूसरे दिन हवन यज्ञ व चौथे दिन 16 जून को नौकरी से हटाए गए योग शिक्षकों व योग सहायकों ने सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए योग शिक्षक कुलदीप आर्य, सत्यवान आर्य व नरेंद्र आर्य ने धरना स्थल पर अपने बालों की आहुति दी।

विभिन्न योग शिक्षकों ने सरकार द्वारा बनाई गई योगशालाओं एवं व्यायामशालाओं की दुर्दशा का बखान करते हुए कहा कि ये पशुओं के बारे जैसे हो गये हैं, जहां नशेड़ियों का डेरा रहता है। योग के नाम पर सरकार विज्ञापनबाजी में करोड़ों रुपया खर्च कर बड़ा घोटाला कर रही है। अगर योग शिक्षक वह सहायक सड़क पर हैं तो योगशाला में योग कैसे संभव होगा?

सरकार विफल हो चुकी है और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के नाम पर सरकार द्वारा सिर्फ ढकोसला किया जा रहा है। योग शिक्षक डिग्रियां हासिल कर आज सड़कों पर बैठे धरना देने को मजबूर हो चुके हैं।

आर्थिक संकट, फासीवाद और मजदूर आंदोलन पर दिल्ली में सेमिनार

नई दिल्ली। इंकलाबी मजदूर केंद्र ने गांधी पीस फाउंडेशन में "आर्थिक संकट फासीवादी विस्तार और मजदूर आंदोलन की चुनौतियां" विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में इंकलाबी मजदूर केंद्र द्वारा एक सेमिनार पत्र भी प्रस्तुत किया गया। उक्त कार्यक्रम में 21 संगठनों के अतिरिक्त सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं प्रोफेसर्स आदि ने भागीदारी किया। कार्यक्रम में भागीदार संगठनों के प्रतिनिधियों ने उक्त विषय पर अलग-अलग कोणों से अपनी बात रखी। सभी प्रतिनिधि वक्ताओं ने बताया कि मौजूदा आर्थिक संकट पूंजीवाद का अपना संकट है। लेकिन इसका दंश बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, गरीबी, महिला हिंसा, भांति भांति के अपराध के रूप में मजदूरों-किसानों सहित गरीब महिलाओं को झेलना पड़ता है।

मौजूदा आर्थिक संकट पूंजी निवेश की कमी के कारण नहीं है, बल्कि उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में आयी भारी गिरावट के कारण पैदा हुआ है। यह दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आर्थिक संकट निजीकरण, उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की नीतियों के द्वारा पूंजीपति वर्ग को मिली 'लूट की छूट' का परिणाम है। 2007-2008 से गहरे संकट में फंसी देश दुनिया की अर्थव्यवस्था को 2020-21 में आयी कोरोना महामारी ने रसातल में पहुंचा दिया है।

अर्थव्यवस्था में आए संकट से पूंजीपति को मुनाफा कमाने का संकट भी आया है। लेकिन अपने देश की मोदी सरकार सहित दूसरे देशों की सरकारों ने पूंजीपति वर्ग के साथ एकजुटता दिखाते हुए अरबों खरबों के आर्थिक पैकेज दिए हैं। इन सरकारों ने पूंजीपति वर्ग को ऋण माफी, कारपोरेट टैक्स में भारी छूट के साथ भांति भांति की अन्य दूसरी रियायतों से मदद की हैं। लेकिन समाज में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी,महिला हिंसा आदि को दूर करने के लिए किसी तरह के कदम उठाने के बजाय मजदूरों- किसानों और अन्य मेहनतकशों के अधिकारों को खत्म करने का ही कानून बनाया है। जिससे समाज में सरकारों एवं पूजीपति वर्ग के खिलाफ असंतोष लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते असंतोष के कारण छिटपुट आंदोलन भी खड़े हो रहे हैं।

मारुति कम्पनी, प्रीकाल कम्पनी,पीएफ कानून के खिलाफ बेंगलुरू में महिला मजदूरों के संघर्ष चर्चित संघर्ष रहे हैं। देश में कृषि कानूनों के खिलाफ 13 महीने चले किसानों के संघर्ष ने मोदी सरकार को किसानों के खिलाफ बने तीनों कृषि कानूनों को वापस करने के लिए मजबूर कर दिया था। देश दुनिया में बढ़ते असंतोष एवं संघर्षों को कुचलने के लिए पूंजीपति वर्ग फासीवादी राज्य कायम करने के लिए लगातार फासीवादी संगठनों को शह दे रहा है।

प्रतिनिधियों ने मोदी सरकार को फासीवादी सरकार बताते हुए आरोप लगाया है कि यह सरकार अपने सहयोगी संगठनों जैसे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिन्दू सेना, एबीवीपी से मिलकर समाज में धार्मिक उन्माद फैलाकर हिंसा को बढ़ावा दे रही है। सरकार सरकारी उद्यमों को पूंजीपतियों को सौंप रही है तथा उन्हें लूटने के लिए रास्ते बना रही है।

मोदी सरकार मजदूरों-किसानों-महिलाओं के अधिकारों पर हमला कर उनके खिलाफ कानून बना रही है। मोदी सरकार के साथ भाजपा की राज्य सरकारों ने बुल्डोजर को इंसाफ का पर्याय बता कर इंसाफ के बहाने अल्पसंख्यकों, दलितों, मजदूरों-मेहनतकशों के घर-मकान-रोजीरोटी पर बुलडोजर चला रही है। बुलडोजर राज फासीवाद का नया हथियार है।

सभी प्रतिनिधियों ने पूंजीवादी-साम्राज्यवादी लूट एवं देश में बढ़ते फासीवादी खतरा पर चिंता व्यक्त किया। सभी ने केंद्रीय मजदूर संगठनों की समझौता परस्ती एवं उनकी दूसरी गम्भीर किस्म की कमजोरियों पर बात की। सभी वक्ताओं ने छोटे संगठनों की सीमाओं को रेखांकित करते हुए एक नया अखिल भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संगठन बनाने पर जोर दिया।

इस सेमिनार में दिल्ली पीपुल्स फोरम के साथी अर्जुन प्रसाद, एफ्टू (न्यू) के साथी पीके शाही, परिवर्तनकामी छात्र संगठन से साथी महेंद्र, श्रमिक संग्राम कमेटी से साथी चंचल, सर्वोदय मंडल से साथी सतीश कुमार, प्रगतिशील महिला एकता केंद्र से साथी हेमलता, इंकलाबी मजदूर केंद्र के साथी संजय मौर्या,साथी श्यामवीर, भारत भविष्य मीडिया के साथी भागीरथ, इफ्टू के साथी अनिमेष दास, जन संघर्ष मंच हरियाणा के साथी पाल सिंह, डीयू के प्रोफेसर सरोज गिरी, मजदूर सहयोग केंद्र के साथी पारोमा, मजदूर अधिकार संगठन के साथी शिवकुमार, भगत सिंह छात्र एकता मंच के साथी राजवीर, समयांतर पत्रिका के संपादक पंकज बिष्ट,भारतीय किसान यूनियन (असली अराजनैतिक) के साथी प्रबल प्रताप शाही, मजदूर पत्रिका की साथी निशा,बेलसोनिका यूनियन(गुडगांव) के साथी अजित आदि अपने वक्तव्य रखे। इफ्टू(सर्वहारा) के साथी किसी इमरजेंसी के कारण सेमिनार में शामिल नहीं हो सके किन्तु संगठन की केन्द्रीय कमेटी की ओर से सेमिनार हेतु संदेश भेजा गया था जिसे संचालक ने सदन को पढ़कर सुनाया।

अध्यक्ष मण्डल में बैठकर साथी अर्जुन प्रसाद,सुदेश कुमारी, पंकज बिष्ट, हेमलता, नरभिंदर सिंह,संजय मौर्या, महेन्द्र कुमार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम का संचालन इमके के महासचिव साथी खीमानंद ने किया। फरीदाबाद से आई इमके की सांस्कृतिक टीम द्वारा क्रांतिकारी गीत प्रस्तुत किया गया।

इंकलाब जिंदाबाद!
इंकलाबी मजदूर केंद्र